

परसीमन

प्रलिस के लयः

परसीमन, परसीमन आयोग अधनयल 1952, भारतीय संवधान, परसीमन आयोग, 15वाँ वतलत आयोग, भारत नरलवाचन आयोग

मेन्स के लयः

परसीमन की आवश्यकता और संबंधतल चतलएँ ।

स्रोतः द हदू

चरचा में कयों?

लोकसभा और राज्य वधानसभाओं के लयल नरलवाचन कषेत्रों का परसीमन वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर कयल जानल है ।

- वर्ष 2021 की जनगणना मूल रूप से कोवडल-19 महामारी और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से देरी के कारण स्थगलत कर दी गई थी ।

परसीमन क्या है?

■ परचयः

- परसीमन का अर्थ है लोकसभा और वधानसभाओं के लयल प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और क्षेत्रीय नरलवाचन कषेत्रों की सीमाएँ तय करने की प्रक्रयल ।
 - इसमें इन सदनों में अनुसूतल जातल (SC) और अनुसूतल जनजातल (ST) के लयल आरक्षण सीटों का नरलधारण भी शामिल है ।
- यह 'परसीमन प्रक्रयल' 'परसीमन आयोग' द्वारा की जातल है जसल संसद के एक अधनयल के तहत स्थापतल कयल जातल है ।
 - 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधनयलों के तहत परसीमन आयोग चार बार स्थापतल कयल गए हैं **वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002** में ।
 - पहला परसीमन कार्य राष्ट्रपतलद्वारा (नरलवाचन आयोग की मदद से) वर्ष 1950-51 में कयल गया था ।

■ ऐतहासकल पृष्ठभूमलः

- लोकसभा की राज्यवार संरचना में परवलरतन लाने वाला अंतलम परसीमन वर्ष 1976 में पूरा हुआ और यह वर्ष **1971 की जनगणना के आधार पर** कयल गया ।
- भारत का संवधान यह आज्ञापतल करता है कल लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होना चाहयल ताकल सीटों का जनसंख्या से अनुपात सभी राज्यों में लगभग सामान हो । इसका उद्देश्य यह सुनशलचतल करना है कल प्रत्येक व्यक्तल के वोट का भारांक लगभग समान हो, भले ही वे कसल भी राज्य में रहते हों ।
 - हालाँकल इस प्रावधान का अर्थ यह था कल जनसंख्या नयलंतरण में कम रूचलरखने वाले राज्यों को संसद में अधिक संख्या में सीटें मलल सकतल हैं ।
- इस तरह के परणालों से बचने के लयल संवधान में संशोधन कयल गया । **42वें संशोधन अधनयल, 1976** ने वर्ष 1971 के परसीमन के आधार पर **वर्ष 2000 तक** के लयल राज्यों में लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशकल नरलवाचन कषेत्रों में वभाजन पर रोक लगा दी ।
- 84वें संशोधन अधनयल, 2001 ने सरकार को वर्ष 1991 की जनगणना के जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर राज्यों क्षेत्रीय नरलवाचन कषेत्रों के पुनर्समायोजन और युक्तलकरण का अधिकार दयल ।
- 87वें संशोधन अधनयल, 2003 में नरलवाचन कषेत्रों के परसीमन का प्रावधान वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर कयल गया, न कल वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ।
 - हालाँकल यह लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटलत सीटों की संख्या में बदलाव कयल बनल कयल जा सकतल है ।

■ संवधानकल प्रावधानः

- **अनुच्छेद 82** के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परसीमन अधनयल बनातल है ।
- **अनुच्छेद 170** के तहत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अधनयल के अनुसार क्षेत्रीयनरलवाचन कषेत्रों में वभाजतल कयल

क्यों महत्त्वपूर्ण है परसीमन?

■ प्रतिनिधित्व:

- परसीमन जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर सीटों की संख्या को समायोजित करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
- यह "एक नागरिक-एक वोट-एक मूल्य" (one citizen-one vote-one value) के लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

■ हस्तिसेदारी:

- परसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः समायोजित करके विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीटों का समान वितरण सुनिश्चित करना है।
- इससे विशिष्ट क्षेत्रों के कम प्रतिनिधित्व या अधिक प्रतिनिधित्व को रोकने में मदद मिलती है।

■ SC/ST के सीटों का आरक्षण:

- परसीमन संवैधानिक प्राधान्यों के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये आरक्षणित सीटों का आवंटन निर्धारित करता है, जिससे हाशिये पर स्थिति समुदायों के लिये पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

■ संघवाद:

- परसीमन राज्यों के बीच राजनीतिक शक्त के वितरण को प्रभावित करके संघीय सिद्धांतों को प्रभावित करता है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिये जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व और संघीय वचारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

■ जनसंख्या नियंत्रण के उपाय:

- ऐतिहासिक रूप से, वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या की स्थिति करने का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करना था। हालाँकि, आसन्न परसीमन प्रक्रिया बदलती जनसांख्यिकी के संदर्भ में इस नीतिकी प्रभावशीलता और नैतिकार्थ पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

परसीमन को लेकर कौन-सी चर्चाएँ वदियमान हैं?

■ क्षेत्रीय असमानता:

- निर्णायक कारक के रूप में जनसंख्या के कारण लोकसभा में भारत के उत्तर और दक्षिणी भाग के बीच प्रतिनिधित्व में असमानता है।
- केवल जनसंख्या पर आधारित परसीमन दक्षिणी राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में की गई प्रगति की अवहेलना करता है और संघीय ढाँचे में असमानताओं का कारण बनता है।
 - देश की जनसंख्या का केवल 18% होने के बावजूद दक्षिणी राज्य देश के सकल घरेलू उत्पाद में 35% योगदान करते हैं।
- उत्तरी राज्य जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता नहीं देते हैं तथा उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण परसीमन प्रक्रिया में उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद है।

■ अपर्याप्त वित्तपोषण:

- 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना को अपनी सफाई के आधार के रूप में उपयोग करने के बाद दक्षिणी राज्यों के संसद में वित्तपोषण और प्रतिनिधित्व खोने के बारे में चर्चा व्यक्त की है।
- इससे पहले 1971 की जनगणना को राज्यों के लिये वित्तपोषण और कर वित्त सफाई के आधार के रूप में उपयोग किया गया था।

■ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को प्रभावित करना:

- सीटों के निर्धारित परसीमन और पुनः आवंटन के परिणामस्वरूप न केवल दक्षिणी राज्यों के लिये सीटों की हानि हो सकती है बल्कि उत्तर में अपने आधार के साथ राजनीतिक दलों के लिये सत्ता में वृद्धि भी हो सकती है।
 - यह संभवतः उत्तर की ओर और दक्षिण से दूर शक्ति का स्थानांतरण कर सकता है।
- यह प्रक्रिया प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिये आरक्षणित सीटों के विभाजन को भी प्रभावित करेगी (अनुच्छेद 330 और 332 के तहत)।

Table 1: If the number of seats is retained at 543 and reapportioned among States based on the projected population in 2026

State	Number of seats at present	Number of seats projected	Net gain/loss
U.P.	80	91	11
Bihar	40	50	10
Rajasthan	25	31	6
M.P.	29	33	4
Tamil Nadu	39	31	-8
Andhra + Telangana	42	34	-8
Kerala	20	12	-8
Karnataka	28	26	-2
Punjab	13	12	-1
Himachal	4	3	-1
Uttarakhand	5	4	-1

Table 2: If the number of seats is increased to 848 based on the projected population in 2026

State	Number of seats at present	Number of seats projected	Net gain
U.P.	80	143	63
Bihar	40	79	39
Rajasthan	25	50	25
M.P.	29	52	23
Tamil Nadu	39	49	10
Andhra + Telangana	42	54	12
Kerala	20	20	-
Karnataka	28	41	13
Punjab	13	18	5
Himachal	4	4	-
Uttarakhand	5	7	2

परसीमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ कौन-सी हैं?

- अमेरिका में:
 - वर्ष 1913 से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (हमारी लोकसभा के समकक्ष) में सीटों की संख्या 435 तक सीमिति कर दी गई है।
 - देश की जनसंख्या वर्ष 1911 के 9.4 करोड़ से लगभग चार गुना बढ़कर वर्ष 2023 में अनुमानतः 33.4 करोड़ हो गई है। **परत्येक जनगणना के बाद 'समान अनुपात की वधि' (method of equal proportion) के माध्यम से राज्यों के बीच सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है।** इससे किसी भी राज्य को कोई महत्वपूर्ण लाभ या हानि नहीं होती है।
 - उदाहरण के लिये, वर्ष 2020 की जनगणना के आधार पर, पुनर्वितरण के परिणामस्वरूप 37 राज्यों की सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- यूरोपीय संघ (EU):
 - 720 सदस्यों वाली यूरोपीय संघ संसद में सीटों की संख्या को 'अधोगामी अनुपातकृति' (Degressive Proportionality) के सिद्धांत के आधार पर 27 सदस्य देशों के बीच वभाजित किया गया है।
 - इस सिद्धांत के तहत, **जनसंख्या बढ़ने पर सीटों की संख्या का अनुपात बढ़ेगा।**
 - उदाहरण के लिये, लगभग 60 लाख की आबादी वाले डेनमार्क में 15 सीटें (प्रतिसदस्य 4 लाख की औसत आबादी) हैं, जबकि 8.3 करोड़ की आबादी वाले जर्मनी में 96 सीटें (प्रतिसदस्य 8.6 लाख की औसत आबादी) हैं।

परसीमन आयोग क्या है?

- नयुक्ति:
 - परसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपतिद्वारा नयुक्ति किया जाता है तथा भारत नरिवाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
- संरचना:
 - [सर्वोच्च न्यायालय](#) के सेवानवृत्त न्यायाधीश
 - [मुख्य नरिवाचन आयुक्त](#)
 - संबंधित राज्य के नरिवाचन आयुक्त
- कार्य:
 - सभी नरिवाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग बराबर करने के लिये नरिवाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का नरिधारण करना।
 - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षणित सीटों की पहचान करना, जहाँ उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है।

■ शक्तियाँ:

- आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में बहुमत की राय प्रबल होती है।
- भारत में परसीमन आयोग एक उच्च-शक्ति प्राप्त निकाय है, जिसके आदेशों को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

आगे की राह

- संघीय वचारों के साथ लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने की आवश्यकता है। सुझावों में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिये स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के साथ-साथ जनसंख्या के आधार पर वधायकों की संख्या में वृद्धिकरते हुए लोकसभा सीटों की संख्या सीमित करना शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न . परसीमन आयोग के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचार कीजयि: (2012)

1. परसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
2. परसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य वधिनसभा के समुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कयिा जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)